भारत के मध्यस्थता हब बनने के भविष्य पर चर्चा

देहरादून, 21 जून (नवोदय टाइम्स) : यूपीईएस स्कूल ऑफ लॉ द्वारा प्रतिष्ठित कानूनी सम्मेलन श्रृंखला एडाप्ट के दूसरे संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस वर्ष की थीम रही 'भारतीय मध्यस्थता एक दोराहे पर सुधार, विरोध और एक मध्यस्थता केंद्र के रूप में भविष्य', जिसके तहत भारत के शीर्ष न्यायविदों, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और उद्योग विशेषज्ञों ने गहन चर्चा की।

कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश विक्रमजीत सेन और हेमंत गुप्ता, अध्यक्ष इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर ने मुख्य भाषण दिए गए। इसके बाद हुई राउंड टेबल चर्चाओं और पैनल सत्रों में भारत की मध्यस्थता प्रणाली के सामने खड़ी संरचनात्मक और सांस्कृतिक चुनौतियों को लेकर व्यापक संवाद हुआ।

सम्मेलन में छह महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श हुआ, जिनमें भारत का बदलता मध्यस्थता रुख, प्रक्रिया में विलंब, मध्यस्थों की जवाबदेही, नैतिकता व स्वायत्तता, न्यायिक हस्तक्षेप, प्रवर्तन की चुनौतियां और भारत का मध्यस्थता हब बनने का भविष्य। यह संवादात्मक मंच विभिन्न पक्षों को एक साथ लाकर भारत में विश्वसनीय और आधुनिक मध्यस्थता व्यवस्था की दिशा में व्यावहारिक सुझावों और समाधान की तलाश में अहम साबित हुआ।

कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हुए डॉ. अभिषेक सिन्हा, डीन, यूपीईएस स्कूल ऑफ लॉ ने कहा, "भारत इस समय मध्यस्थता की दिशा में एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। एडाप्ट या पेरिश जैसे आयोजनों के माध्यम से हम विचारशील और क्रियाशील लोगों को एक मंच पर लाकर सिस्टम की खामियों पर चर्चा और सुधार की संभावनाओं को तलाशने का प्रयास कर रहे हैं।

वर्षों से यूपीईएस स्कूल ऑफ लॉ ने टेक्नोलॉजी-संचालित उत्कृष्ट विधिक शिक्षा का उदाहरण प्रस्तुत किया है।

ये रहे मौजूद

अक्षय शर्मा, पार्टनर, एसएएम, न्यायमूर्ति जेआर मेधा, पूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय, मनन शुक्ला, पार्टनर, एवएसए, गौहर मिर्जा, पार्टनर, सीएएम, नवीन कुमार सिंह, सीईओ, इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इंडिया, न्यायमूर्ति रेखा पल्ली, पूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय, जाफर खुर्शीद, वरिष्ठ पार्टनर, आईपी वेयर, टीकेसी पार्टनर्स, पलक नागर, प्रिंसिपल एसोसिएट, विवाद समाधान, सीएएम।